

(xiii) Western Paques (India) Ltd. has signed an MOU with Ho Chi Minh and Hanoi Municipality Corporation, Vietnam to process municipal solid waste to solve long unresolved environmental hazard of waste disposal problem of Ho Chi Minh city and produce energy and manure as a by-product. Western Paques have also signed MOUs with the Municipal Corporation of Ankara City (Turkey), Istanbul City (Turkey) and Chiang Mai city (Thailand).

(xiv) MOU between M/s. Thermochem Inc., California, USA and M/s. Ajinkya Tara Cooperative Sugar Mills, Maharashtra for a 10 MW Power Project through bagasse gasification.

(xv) MOU between M/s. CTBR, France and M/s. Esquire Energy Ltd., Bombay for projects in sugar mills for bagasse cogeneration.

(xvi) A technical collaboration venture between Tata BP Solar (Pvt.) Ltd., Bangalore and BP Solar UK for manufacturing solar photovoltaic modules and systems with an installed capacity of 1 MW per year has been set up at Electronic City, Bangalore.

(xvii) M/s. Webel-SL Energy Systems, West Bengal and Helios of Italy are setting up a project for manufacturing of solar cells, photovoltaic modules and systems.

(xviii) M/s. Eco Solar, Pune is working with University of Colorado, USA for developing Cadmium Telluride-based Photovoltaic Modules with an annual capacity of 700 KW.

(xix) M/s. Sun Source Cannon Energy Ltd., India and M/s. Canan Power Corp., USA are setting up a joint venture at a total cost of Rs. 60 crores for alternate energy project like solar, wind etc. in India.

(xx) M/s. Owimax Services India Ltd. and M/s. Owimax of Russia are setting up a joint venture for providing services in India in the field of photovoltaics, semiconductors, non-conventional energy sources and pollution control.

(xxi) M/s. Peerless Developers Ltd., Calcutta and M/s. Frazer Nash Research Ltd., U.K. are starting a joint venture for manufacture of solar passenger transport vehicles powered by batteries, supplemented by photovoltaic charging.

पदाधिकारियों के विरुद्ध गठित किए गए जांच आयोग

1452. श्री नागमणि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों के दौरान सार्वजनिक जीवन में कार्यरत शीर्ष पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने, विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यक्रमों इत्यादि में दोषों और कमियों की जांच करने और इनमें सुधार करने हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से कुल कितने आयोग कब-कब और किन-किन मामलों में गठित किए गए थे ;

(ख) कितने आयोगों की सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही पूरी की गई है और कितने आयोगों की सिफारिशों पर आंशिक रूप से कार्यवाही की गई है और कितने आयोगों की सिफारिशों पर कार्यवाही अभी भी लम्बित है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे आयोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है अथवा तैयार किए जाने का प्रस्ताव है ?

कामिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारयेड आल्वा) (क) इस मंत्रालय ने पिछले 10 वर्षों में किसी भी शीर्ष पदाधिकारी

के विरुद्ध कोई भी जांच आयोग स्थापित नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Corporation cases against Government officials registered by CBI

1453 SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the CBI has registered cases of corruption against several Government officials during the past three months;

(b) if so, the details thereof and the charges registered against them; and

(c) what punitive action Government propose to take against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA):

(a) Yes, Sir.

(b) 323 cases of corruption were registered against 571 Govt. officials during the last 3 months i.e. August to October, 1994. Out of 323 cases, investigation in 60 cases has so far been finalised. Out of 60 cases finalised, 30 cases were sent up for trial, 29 cases were referred to the Depts. concerned for initiating Regular Departmental Action and one case was closed for want of sufficient evidence.

(c) Action against such officers depends on the outcome of judicial trials and/or regular department action, which are quasi-judicial in nature.

कापार्ट द्वारा बिहार में स्वीकृत की गई योजनाएँ

1454. श्री रामदेव भंडारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1994 से अब तक कापार्ट द्वारा मधुबनी (बिहार) में स्वयंसेवी संस्थाओं को स्वीकृत की गई योजनाओं और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या-क्या है और योजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) कितनी संस्थाओं के विरुद्ध धनराशि के दुर्विनियोग की जांच चल रही है ; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) बिहार के मधुबनी जिले में कापार्ट द्वारा 1. 4. 1994 से 31. 10. 1994 तक स्वयंसेवी संस्थाओं को दी गई सहायता, स्वीकृत की गई योजनाएँ, स्वीकृत की गई धनराशि एवं जारी की गई धनराशि एवं स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। नीचे देखिए)

(ख) बिहार के मधुबनी जिले में कापार्ट द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी स्वयंसेवी संस्था के विरुद्ध धनराशि के दुर्विनियोग के लिए पृच्छताछ का कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।